भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4994
01 अप्रैल, 2022 **को उत्तर के लिए**

रक्षा भूमि पर सिविल परियोजनाएं

4994.**श्री तेजस्वी सूर्या :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2014 के बाद से बेंगलुरु में सड़क निर्माण, मेट्रो निर्माण, पाइपलाइन बिछाने, वन भूमि में परिवर्तन, झील पुनर्विकास आदि जैसी सिविल परियोजनाओं के लिए रक्षा भूमि में दी गई अनुमतियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या मंत्रालय को बेंगलुरु में सिविल परियोजनाओं के लिए भूमि देने के लिए कोई मुआवजा प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) बेंगलुरु में रक्षा भूमि पर सिविल परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति के लिए लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है और इसमें तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) बेंगलुरु में उपलब्ध रक्षा भूमि कितनी है ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अजय भट्ट)

(क): ऐसे 25 मामले हैं जिनमें बेंगलुरु में 2014 के बाद से रक्षा भूमि पर सड़क निर्माण, मेट्रो निर्माण, पाइपलाइन बिछाने, वन भूमि में परिवर्तन, झील पुनर्विकास आदि जैसी सिविल परियोजनाओं के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कार्य करने की अनुमति/सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

(ख) जी, हां । ऐसी रक्षा भूमि से प्राप्त मुआवजे का विवरण निम्नानुसार हैः

i. 123,05,12,057/- रुपए मूल्य का नकद मुआवजा प्राप्त हुआ है ।
ii. वर्ष 2014 से दिनांक 29.03.2022 तक पट्टा किराए के लिए 7,49,67,855/- रुपए और लाइसेंस शुल्क के लिए 1,24,433/- रुपए मूल्य की धनराशि प्राप्त हुई है ।
iii. 305.75 करोड़ रुपए की समान मूल्य भूमि(ईवीएल) की कुल रक्षा भूमि में से राज्य सरकार द्वारा 232,52,29,197 रुपए मूल्य की ईवीएल का प्रस्ताव दिया गया है और भूमि रक्षा मंत्रालय के अधीन है ।

(ग) बेंगलुरु में रक्षा भूमि पर सिविल परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए 01 आवेदन अनुमति के लिए लंबित है। उक्त आवेदन प्रारंभिक रूप से दिनांक 03.09.2021 को रक्षा मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुआ था। रक्षा मंत्रालय में प्रस्ताव पर विस्तृत जांच के बाद दिनांक 11.10.2021 को हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई थी। इसके उपरांत, मांग करने वाली एजेंसी से दिनांक 03.01.2022 को स्पष्टीकरण मांगा गया था। आईए की टिप्पणी दिनांक 05.01.2022 को प्राप्त हुई थी। दिनांक 19.01.2022 को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मामले पर दोबारा चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि सुरक्षा कारणों से मांग करने वाली एंजेसी संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। संशोधित प्रस्ताव दिनांक 15.02.2022 को प्राप्त हुआ है।

(घ) बेंगलुरु में कुल 9188.62 एकड़ रक्षा भूमि रक्षा मंत्रालय के अधीन है।

****